विचार बिन्दु

स्मृति पीछे दृष्टि डालती है और आशा आगे। –रामचंद्र टंडन

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की नैतिकता संकट में

राजस्थान में चिकित्सा तंत्र आज घोर संकट की तस्वीर पेश कर रहा है, और विशेषकर राजधानी जयपुर भी इससे अनछुआ नहीं हैं। हाल के खुलासों, मीडिया रिपोर्टों और शोधों ने यह प्रमाणित किया है कि जहाँ चिकित्सा का मूल उद्देश्य रोगी की भलाई होना चाहिए, वहीं कहीं-कहीं इलाज का लक्ष्य लाभ बन गया है। बड़े निजी अस्पतालों में अनावश्यक भर्ती, जांच और ऑपरेशनों की बढ़ती प्रवृत्ति, बीमा घोटाले, दवा उद्योग तथा चिकित्सकों के बीच सांठ-गाठ और अंग-तस्करी जैसी वीभत्स घटनाएँ रोगी-हित की हिफ़ाज़त करने वाली व्यवस्था की मौलिक कमजोरियों को उजागर करती हैं। राजस्थान के ग्रामीण व शहरी दोनों हिस्सों में यह संकट अलग-अलग रूपों में उभर रहा है और जयपुर, जहाँ चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र है, इन समस्याओं के सामने एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशनों की असामान्य रूप से ऊँची सूचियाँ जैसे हायस्टेरेक्टॉमी, सी-सेक्शन, हृदय सर्जरी और अर्थ्रोप्लास्टी केवल चिकित्सकीय प्रवृत्ति का मामला नहीं हैं; यह उस व्यवस्था का संकेत हैं जिसमें आर्थिक प्रोत्साहन चिकित्सकीय निर्णयों में घुस आते हैं। जयपुर जैसे महानगरों में उच्च-प्रोफाइल निजी संस्थान और कुछ वरिष्ठ चिकित्सक जिनकी पारिश्रमिकें कई गुना होती हैं, का प्रभाव निर्णय-प्रक्रिया पर दिखाई देता है। राजधानी के पास उपलब्ध विशेषज्ञता और उन्नत सुविधाएँ ग्रामीण मरीजों को आकर्षित करती हैं, पर साथ ही अनावश्यक प्रक्रियाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है-क्योंकि दूर-दराज के लोग मामूली बीमारी के लिए बड़े शहर आकर विशेषज्ञों पर निर्भर हो जाते हैं और अक्सर उनके पास विकल्पों की कमी रहती है।

बीमा प्रणाली, जो मूलतः आर्थिक सुरक्षा और चिकित्सा तक पहुँच का जरिया है, कई मामलों में भरोसे के संकट में बदल चुकी है। जयपुर के कुछ केसों में क्लेम अस्वीकार किए जाने, प्रक्रियागत बाधाओं और विवादित बिलिंग के आरोप सामने आए हैं, जिनसे लोगों का विश्वास मंझला हुआ है। कोविड-19 के समय में देशव्यापी जैसे कुछ आरोपों ने यह दिखाया कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी पारदर्शिता लचीली हो सकती है। राजधानी के आस-पास के जिलों से आई शिकायतें इस बात का संकेत हैं कि बीमा और निजी अस्पताल के बीच के व्यवहार ने विशेषकर मध्यम आय वर्ग और गरीब रोगियों की बचत पर चोट की है।

लैब व डायग्नोस्टिक रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर उठते सवाल और कुछ पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं के खतरनाक खेल ने चिकित्सा विज्ञान के आधार को भी हिला दिया है। जयपुर में किए गए कुछ छापे और जांचें इस ओर इशारा करती हैं कि नकदी लेनदेन और अनियमित रिपोर्टिंग जैसी प्रथाएँ मौजूद रही हैं। जब परीक्षण ही संदिग्ध हों तो निदान और उपचार दोनों प्रभावित होते हैं। छोटे शहरों व गांवों के मरीज जो जयपुर की लैबों पर भरोसा कर रिपोर्ट बनवाते हैं, वे गलत रिपोर्ट के कारण अनावश्यक दवाइयों और सर्जिकल प्रक्रियाओं के शिकार बन सकते हैं।

फार्मा उद्योग और चिकित्सकीय पेशे के बीच हितों का टकराव भी गंभीर रूप ले चुका है। ब्रांडेड दवाओं के प्रचार और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियों के बहाने चिकित्सकीय निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। जयपुर की कॉरपोरेट क्लिनिक-हब संस्कृति में, जहां दवा कंपनियों की गतिविधियाँ ज्यादा दिखाई देती हैं, मरीजों को महँगी दवाएँ दी जाने के आरोप उभरते रहे हैं जबकि जेनरिक विकल्प उपलब्ध और प्रभावी होते। अस्पतालों का दवा और उपकरण पर मार्जिन तथा बिलिंग में पारदर्शिता का अभाव राजधानी के मध्यम और निम्न आय वर्ग परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है।

सबसे भयावह पक्ष अंग-तस्करी और मानव शोषण के मामले हैं। राजस्थान के सीमांत इलाकों से जुड़े कुछ नेटवर्क ने कभी-कभी जयपुर के अस्पतालों व क्लिनिकों को भी अपने कामकाज के लिए उपयोग किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि महानगर का चिकित्सा-इकोसिस्टम अपराधी नेटवर्क के संपर्क में आ सकता है। नौकरी या इलाज के नाम पर बहलाकर लाने, फर्जी भर्ती और परीक्षण कराकर अंगों के अवैध व्यापार में डालने जैसे कृत्य केवल कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता पर चोट हैं। ऐसे मामलों में अस्पतालों, चिकित्सकों और एजेंटों के आपसी नेटवर्क का होना चिंतनीय है और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा पर गहरा असर डालता है।

पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स का प्रमाणन और नियमित निरीक्षण तेज करना होगा। केवल प्रमाणित लैबों को सरकारी या बीमा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देनी चाहिए, और अनियमितता पाई जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जयपुर में नियमित आकस्मिक निरीक्षण, सैंपल-ऑडिट और नागरिक शिकायत तंत्र प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय हैं।

नियमों और नियामक संस्थाओं की कमजोरी इन कुप्रथाओं को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। मेडिकल शिक्षा और अस्पतालों के लाइसेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्थाएँ, जिनसे मानक और गुणवत्ता की उम्मीद रहती है, कई बार संसाधन की कमी, अनुपालन की लापरवाही या राजनीतिक दबाव के कारण कड़ी निगरानी नहीं कर पातीं। जयपुर में नई निजी मेडिकल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के त्वरित उदय ने मानकीकरण और नियमित निरीक्षण की आवश्यकता को और बल दिया है। पारदर्शिता की कमी और नियमों का ढीलापन ही उन प्रथाओं को पोषित करता है जो चिकित्सा की मूल नैतिकता को चुनौती देती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुस्तरीय और तत्काल सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, चिकित्सा और अस्पतालों के वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता अनिवार्य की जानी चाहिए। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को सार्वभौमिक व केंद्रीकृत बनाया जाना चाहिए ताकि हर जांच, इलाज और सर्जरी का रिकॉर्ड टिकाऊ और सार्वजनिक ऑडिट के लिए उपलब्ध रहे। जयपुर में डिजिटल इंटीग्रेशन मॉडल को पूरे राज्य में फैलाया जा सकता है राज्य सरकार और लोक स्वास्थ्य निकायों को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहिए। इससे फर्जी रिपोर्ट, बिना सहमति के सर्जरी और नकली क्लेम की पहचान में मदद मिलेगी।

क्लिनिकल निर्णयों पर बाहरी निगरानी और नियमित क्लिनिकल ऑडिट लागू किया जाना चाहिए। जयपुर जैसे बड़े शहरी केंद्रों में उच्च-जोखिम वाले ऑपरेशनों के लिए स्वतंत्र चिकित्सकीय समितियों से पूर्व अनुमति जैसी प्रक्रियाएँ लागू कर के अनावश्यक सर्जरी घटाई जा सकती हैं। रेफरल और अन्य आर्थिक प्रोत्साहनों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और इस तरह के भुगतान के खुलासे पर सख्त सीमाएँ लगनी चाहिए।

पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स का प्रमाणन और नियमित निरीक्षण तेज करना होगा। केवल प्रमाणित लैबों को सरकारी या बीमा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने की अनुमति देनी चाहिए, और अनियमितता पाई जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जयपुर में नियमित आकस्मिक निरीक्षण, सैंपल-ऑडिट और नागरिक शिकायत तंत्र प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय हैं।

फार्मा कंपनियों और चिकित्सा पेशे के बीच हित-टकराव पर कड़ा नियंत्रण लागू होना चाहिए। चिकित्सकों को जेनरिक दवाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जाए और प्रलोभन स्वीकारने वालों पर सख्त दंडात्मक प्रावधान हों। मेडिकल शिक्षा में नैतिकता और पारदर्शिता की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ पेशेवर ईमानदारी को प्राथमिकता दें। जयपुर के मेडिकल कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान इस पाठ्यक्रम को मॉडल बनाकर पूरे राज्य में प्रसारित कर सकते हैं।

अंग-तस्करी व मानव शोषण के मामलों के लिए त्वरित और विशेष जांच-प्रक्रियाएँ जरूरी हैं। पुलिस-स्वास्थ्य विभाग समन्वय को मजबूत किया जाए और पीड़ितों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील हेल्पलाइन व संरक्षण-प्रणालियाँ लागू की जाएँ। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी व पंजीकृत कराना होगा ताकि रोजगार के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगे। जयपुर में समर्पित कैंपेन और जागरूकता कार्यक्रम निशचित रूप से प्रभावी साबित हो सकते हैं, विशेषकर जब स्थानीय सामाजिक संस्थाएँ और पंचायतें साथ दें।

मरीजों की जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है। मरीजों को इलाज के विकल्प, अनुमानित लागत, संभावित जोखिम और वैकल्पिक उपचारों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रभावी नागरिक शिकायत निवारण पैनल जिनमें विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हों, तेज़ और निष्पक्ष निर्णय दें। स्वतंत्र मीडिया व जनजागरूकता अभियानों की भूमिका को बढ़ावा देना होगा क्योंकि खबरों और सार्वजनिक खुलासों ने कई कुख्यात प्रकरणों को उजागर किया है। जयपुर के स्थानीय मीडिया और नागरिक मंच इस दिशा में सक्रिय रहकर राज्यव्यापी प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

राजस्थान में चिकित्सा तंत्र की गरिमा और समाज का विश्वास तभी बहाल होगा जब नीति-निर्माण, कड़ा नियमन, तकनीकी पारदर्शिता और नैतिकता पर एक साथ जोर दिया जाए। अस्पताल और डॉक्टर सिर्फ बीमारी का उपचारक नहीं, समाज के भरोसे के रखवाले भी हैं। जब तक यह भरोसा लौटकर नहीं आता, तब तक स्वास्थ्य तंत्र में व्यापक रूप से जोखिम बना रहेगा और मरीजों, परिवारों तथा समाज को जो गहरी चोटें आई हैं, उनका पूरी तरह मरम्मत कठिन होगी। समय पर ठोस संवैधानिक व प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक सतर्कता ही इस पतन को रोकने का मार्ग हैं अन्यथा स्वास्थ्य की सुविधा और मानवता दोनों की कीमत चुकानी पड़ेगी।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

बेटा 27 का, बेरोजगार... लड़की वाले मना कर गए!

कक्षा 10 के बाद कलम के साथ कारीगरी, तभी बसेगा घर

मदन सिंह काला

55 लाख सरकारी कुर्सियाँ खाली हैं। 65 करोड़ युवा भटक रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। 27 साल का बेटा। घर में तनाव। लड़की वाले आए, चाय-नाश्ता करते हुए पूछ लिया 'बेटा करते क्या हो?'। जवाब मिला– ''सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ सर''। बस रिश्ता यहीं खटाई में पड़ गया। ये कहानी हर गली-मोहल्ले की है।

3 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप की इथियोपिया-मोरक्को के भूभाग पर आधुनिक मानव -होमो सेपियंस- के रूप में विकसित हुआ। 2017 में नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार मोरक्को के जेबेल इरहूद में मिली 3 लाख साल पुरानी खोपड़ी इसका प्रमाण है। उसका माथा ऊँचा था, ठुड्डी उभरी हुई थी, दिमाग 1350 ग्राम का था। 65 हजार साल पहले उसका एक समूह अरब सागर के किनारे-किनारे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप पहुँचा। गुजरात के तट से उतरकर वह पूरे भारत में फैल गया। आज भी 50 से 65 प्रतिशत भारतीयों का डीएनए एक है। मतलब हम सबके पूर्वज एक हैं। फिर जाति-धर्म की दीवार क्यों? ये दीवार 200 साल पहले अंग्रेजों की औद्योगिक जरूरत थी। 1871 की जनगणना में हर आदमी को एक खाने में बंद कर दिया – ''लुहार का बेटा लुहार ही रहेगा''। फैक्ट्री में मशीन महंगी थी, ट्रेनिंग कौन दे? इसलिए ''बाप का काम, बेटे का काम'' का नियम थोप दिया। वो 200 साल की मजबूरी थी, 1000 साल का विश्वास नहीं। आज हाथ में स्किल होगी तो जाति पूछने वाला शर्माएगा। क्योंकि पेट जाति नहीं देखता, पेट रोटी देखता है। और रोटी स्किल से बनती है, जाति से नहीं।

उसी मानव ने अनाज उगाया, गाय पाली। अनाज ज्यादा हुआ तो 'बार्टर' चला – गेहूँ दो, दूध लो। हिसाब बराबर न हो तो झगड़ा हो, इसलिए 600 ईसा पूर्व तुर्की की लिडिया घाटी में पहला सिक्का बना। भारत में 2500 साल पहले मगध के राजा बिम्बिसार-अजातशत्रु के समय पंचमार्क सिक्के चले। इन्हें 'आहत सिक्के' कहते थे क्योंकि चाँदी की पत्ती काटकर हथौड़े से सूर्य, बैल, हाथी के ठप्पे लगाए जाते थे। ये राजा के नाम के सिक्के नहीं थे, व्यापारी संघ और मगध-कौशल जैसी सरकारों ने ढाले। बाद में मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त-अशोक के समय ये सरकारी मुद्रा बने। इसी सिक्के ने व्यापार को जन्म दिया, व्यापार से मण्डी बनी, मण्डी से भट्ठी जली और उद्योग खड़े हुए। मानव ने हाथ से मशीन तक की यात्रा की। काम बदला तो समाज बदला, समाज बदला तो रिश्ते बदले। हजारों साल स्त्री चूल्हे-चौके तक सीमित रही क्योंकि काम अलग थे। पुरुष खेत-जंगल, स्त्री घर-आँगन। मिलते ही नहीं थे तो पहचान कैसे होती। इसलिए शादी माँ-बाप, पण्डित, कुण्डली तय करते थे। जाति देखी जाती थी, आचरण नहीं। फिर औद्योगिक क्रान्ति आई। इंग्लैण्ड की कपड़ा मिल हो या जापान की सिल्क फैक्ट्री, जब लड़का-लड़की 8 घण्टे एक मशीन पर खड़े हुए तो तीन बदलाव हुए। स्त्री के हाथ में तनख्वाह आई तो वह बोझ से सहारा बन गई। उसे 'फलाँ की बेटी' की जगह ''एना – मशीन ऑपरेटर'' कहा जाने लगा। रोज 8 घण्टे साथ काम होगा तो लड़का-लड़की एक-दूसरे का गुस्सा, ईमानदारी, मेहनत देख लेंगे। कुण्डली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्मनी में आज 40 प्रतिशत शादियाँ ऑफिस-फैक्ट्री में होती हैं। वहाँ कोई नहीं पूछता तुम कौन सी जाति हो, पूछते हैं ''तुम प्रोजेक्ट हैंडल कैसे करते हो?'' यानी काम की जिम्मेदारी कैसे निभाती हो। मतलब साफ है – जब स्त्री-पुरुष साथ काम करेंगे तो जीवनसाथी का चुनाव कुण्डली से नहीं, आचरण से होगा। जाति और दहेज दोनों अपने आप खत्म हो जाएँगे।

-पाठक से सवालः आपके घर का 18-25 साल का युवा क्या कर रहा है?-

60 साल से अधिक उम्र के लोग जब विद्यार्थी थे तो माता-पिता के साथ खेत में हल चलाते थे, दुकान पर सामान तोलते थे। सुबह स्कूल जाते थे, शाम को खेत-खलिहान या दुकान पर हाथ बटाते थे। इसी शारीरिक श्रम से उनमें जिम्मेदारी, परिश्रम, समय की कद्र के संस्कार विकसित हुए। 10 साल की उम्र में बैल को चारा डालना, 15 साल में हल चलाना सीख गए थे। इसलिए वह पीढ़ी संघर्ष समझती है, पसीने की कीमत जानती है। आज का युवा कक्षा 10 पास कर निकलता है तो उसने जीवन में कभी एक ईंट नहीं लगाई, कभी 100 रुपये की बिक्री नहीं की। उसे स्किल सीखने का मौका ही नहीं मिला। हाथ से काम नहीं करेगा तो मेहनत की आदत कहाँ से आएगी। इसलिए कक्षा 10 पास करने के बाद पढ़ाई के साथ जीवनयापन युक्त रोजगार देना देशहित में अति आवश्यक है।

यदि युवाओं को कक्षा 10 के बाद पढ़ाई के साथ रोजगार मिल जाए तो संविधान की प्रस्तावना के 'तीनों न्याय' में से आर्थिक न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी संविधान प्रस्तावना कहती है – हम भारत के लोग, भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जब 18 साल का युवा कक्षा 10 के बाद 20 हजार रुपये कमाने लगेगा तो वह आर्थिक न्याय की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। बिना रोजगार के प्रस्तावना का 'आर्थिक न्याय' कागज पर ही रह जाएगा।

55 लाख खाली कुर्सियों का लेखा-जोखा

केन्द्र-राज्य-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-पंचायत में 1.8 करोड़ पद स्वीकृत हैं, पर 55 लाख कुर्सियाँ आज भी खाली पड़ी हैं। फिर भी सरकारी खजाने से 3.5 करोड़ लोग वेतन-पेन्शन उठा रहे हैं – इसमें सेवारत 1.25 करोड़ कर्मचारी, 1 करोड़ पेन्शनर और 1.25 करोड़ ठेका-संविदा-आँगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ता जैसे अद्धर्सरकारी लोग शामिल हैं। यानी कुर्सी 1.8 करोड़ की है, पर बोझ 3.5 करोड़ का। 50 प्रतिशत नई भर्ती अब ठेके-अनुबन्ध पर हो रही है, परमानेण्ट नहीं। ठेके पर काम करने वाले युवाओं का शोषण होता है, उन्हें परिवार चलाने का पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, न भविष्य की सुरक्षा मिलती है। ये 55 लाख खाली पद अगर कक्षा 10 के बाद "Dual Work System" से भरे जाएँ तो 18 साल का युवा अप्रेण्टिस बनकर 20 हजार कमा लेगा। न वो बेरोजगार कहलाएगा, न सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ेगा। कुर्सी भरेगी, युवा बसेगा, देश बसेगा।

जर्मनी में कक्षा 10 के बाद 70 प्रतिशत बच्चे 'ड्युअल सिस्टम' में चले जाते हैं। सप्ताह में तीन दिन कम्पनी में मशीन चलाते हैं, दो दिन स्कूल जाते हैं। महीने के अन्त में एक लाख रुपये स्टाइपेण्ड लेते हैं। 18 साल का लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, पीजी यानी किराये का कमरा लेता है, बाइक लेता है। बेरोजगारी 3 प्रतिशत है। स्विट्जरलैण्ड में 60 प्रतिशत युवा 16 साल के बाद बैंक और फैक्ट्री में व्यावसायिक शिक्षा करते हैं। स्टाइपेण्ड सवा लाख रुपये महीना मिलता है। लड़की 20 साल की उम्र में बैंक में 90 हजार कमाती है इसलिए शादी समानता की होती है, समझौते की नहीं। जापान ने 15 साल के बच्चों को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम सिखाया। इन 25 से ज्यादा देशों का एक मन्त्र है – कक्षा 10 के बाद भटकाव नहीं, स्किल। जर्मनी का 18 साल का लड़का 1 लाख महीना कमाता है। भारत का 27 साल का लड़का 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलता है। शर्म किसे आनी चाहिए?

एनसीआरबी का डेटा कहता है 18 से 25 साल के युवाओं की कुल अपराध में भागीदारी 45 प्रतिशत है। क्यों? क्योंकि जर्मनी का युवा 16 से काम कर रहा है, भारत का युवा 18 से 25 तक 'तैयारी कर रहा हूँ' बोलकर खाली बैठा है। खाली दिमाग में शैतानियत का उदय होता है। भारत की धरती में 41.7 अरब टन हाइड्रोकार्बन, 1.23 करोड़ टन लिथियम है। पर तेल का सिर्फ 6-8 प्रतिशत निकल रहा है। हम कच्चा लोहा 40 रुपये किलो बेचकर चीन से स्टील 400 रुपये किलो खरीदते हैं। फर्क सिर्फ गलाने वाले हाथ का है। फैक्ट्रियाँ हैं पर 40 प्रतिशत पद खाली हैं क्योंकि 10वीं पास सीएनसी मशीन नहीं चला पाता। इम्पोर्टर को 10 सेल्समैन चाहिए, मैन्युफैक्चर को 1000 मजदूर। हर साल 6 लाख करोड़ रुपये के हथियार बाहर से मँगाते हैं। एक लड़ाकू विमान 800 करोड़ का। अगर यही हाल हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल में बने तो 20 हजार युवा को रोजगार मिले और वही पैसा आइएसआरओ में लगे। जापान ने 1945 के बाद हथियार नहीं बनाए, स्किल बनाई और आज कार बेचता है। हम स्किल नहीं दे रहे इसलिए आज भी खरीद रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक 13.5 लाख करोड़ रुपये का व्यापार घाटा। मतलब हम दुनिया को कर्ज का कागज देते हैं, बदले में माल लेते हैं।

नतीजा सामने है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 15 से 35 साल के बीच 65 करोड़ युवा। हर साल 1.8 करोड़ बच्चे कक्षा 10 पास करके निकलते हैं। उनमें से 60 प्रतिशत न कॉलेज जा पाते हैं, न कोई हुनर सीख पाते हैं। 3 साल तक भटकते हैं। 18 साल की उम्र में न डिग्री, न स्किल, न तनख्वाह। छोटे किसान की औसत आय 10,218 रुपये महीना है। युवा खेती को मनरेगा वाला मजदूरी समझता है। उसे पता नहीं कौशाम्बी का किसान ग्रीनहाउस टमाटर से 35 लाख सालाना कमा रहा है। फर्क स्किल का है। युवा 10 साल सरकारी नौकरी का इन्तजार करता है और 18 की उम्र 28 हो जाती है। लड़की वाले ओवरएज कहकर मना कर देते हैं। खाली दिमाग में शैतानियत का उदय होता है इसलिए 18 से 25 साल के युवाओं का अपराध 45 प्रतिशत है। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है सम्मान से जीने का अधिकार, अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। पर बिना रोजगार के न इज्जत है, न रोटी, न रिश्ता। 50 करोड़ युवा रोज 2.5-3 घण्टे रील्स देखते हैं। 1 साल में 1000 घण्टे बर्बाद। उसी 1000 घण्टे में कोई लड़का , कोडिंग, ड्रोन पायलट बन जाता। लघु वीडियो बुरे नहीं हैं। स्विट्जरलैण्ड का युवा दिन में 8 घण्टे स्विस घड़ी बनाता है और रात में 30 मिनट देखता है। हमारा युवा दिन में 8 घण्टे रील्स देखता है और रात में 30 मिनट नौकरी की टेन्शन लेता है। लघु वीडियो बनाने वाला 2 साल बाद बेरोजगार क्रिएटर कहलाता है, सीएनसी चलाने वाला 2 साल बाद स्किल्ड टेक्निशियन कहलाता है। शादी के मण्डप में कौन बैठेगा आप खुद सोचिए। मोबाइल युवा का दुश्मन नहीं, दिशा का दुश्मन है। मोबाइल से लघु वीडियो बनाओ पर लघु वीडियो के लिए मोबाइल मत बनो। हाथ में स्किल होगी तो लघु वीडियो तुम्हें ढूँढेंगे, तुम लघु वीडियो को नहीं।

पर उम्मीद अभी बाकी है क्योंकि दुनिया के महान लोगों ने भी यही रास्ता अपनाया था। महात्मा गांधी लन्दन में बैरिस्टर पढ़ते समय खुद झाड़ू लगाते, जूते पॉलिश करते थे। दोस्त हँसते थे ''मोहन, तू बैरिस्टर बनेगा या मोची?'' गांधी कहते – ''जो हाथ कलम पकड़ेगा, वह हाथ झाड़ू भी पकड़ेगा। श्रम की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है''। डॉ. कलाम 8 साल की उम्र में अखबार बेचते थे। रतन टाटा कॉर्नेल से पढ़कर लौटे तो 6 महीने जमशेदपुर की भट्ठी के पास लोहा गलवाया। धीरूभाई अम्बानी 14 साल की उम्र में यमन में पेट्रोल पम्प पर अटेण्डेण्ट थे। बराक ओबामा गर्मियों में आइसक्रीम बेचते थे। स्टीव जॉब्स अटारी में रात की शिफ्ट में गेम के बग ढूँढते थे। एलन मस्क 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बनाकर बेच दिया। सुन्दर पिचाई पढ़ते समय ट्ययूशन पढ़ाकर फीस भरते थे। इन कहानियों की एक सीख है। न कलाम शरमाए कि मैं अखबार वाला हूँ, न गांधी शरमाए कि मैं मोची हूँ। सबने काम को इज्जत दी, इसलिए काम ने उन्हें इज्जत दी। आज भारत का 10वीं पास लड़का आईटीआई में एडमिशन लेते समय शरमा जाता है। अरे भाई, रतन टाटा ने भट्ठी जलाई थी, तुम सीएनसी क्यों नहीं चला सकते।

कबीर का मानव शक्ति के उपयोग के लिए आव्हान आलसी पीढ़ी और सरकार दोनों के लिए हैः –''काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होयगी, बहुरी करेगो कब।''– यानी कल नहीं, आज नहीं – अभी। 18 साल का लड़का आईटीआई का फॉर्म कल भरेगा तो 27 साल 'तैयारी' में निकल जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 41 कहता है राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये प्रयास अब कर्तव्य बनना चाहिए। इसलिए ठउ्र्ल्ल ेदे० एबूस्ठ को भारत में प्राथमिकता से लागू किया जाए। कक्षा 10 के बाद कलम ६ कारीगरी अनिवार्य हो। कबीर का दर्शन अहंकार मिटाने का हैः –''करता था तो डरता था, अब करता हूँ डर नाहिं। जब 'मैं' था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं।''– यानी जब तक ''मैं बीए वाला हूँ, छोटा काम है'' का अहंकार है तब तक डर लगा रहेगा। अहंकार मिटे तो 18 साल में ही निर्भय होकर स्किल सीख लेगा। कबीर का कर्म सिद्धांत भी यही कहता हैः –''करता था तो क्यूं रहया, जब करि क्यूं पछिताय। बोये पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाया।''– यानी स्किल सीखने का समय था तब चुप क्यों बैठा रहा? अब ''नौकरी नहीं मिल रही'' बोलकर पछता क्यों रहा है? बबूल बोया – बीए की डिग्री। आम खाना है तो आम का पेड़ बोओ – आईटीआई, स्किल। तुलसी की चेतावनी भी यही हैः –''सकल पदार्थ है जग मांही, कर्महीन नर पावत नाहीं।''– यानी दुनिया की सारी दौलत यहीं पड़ी है। पर कर्महीन, स्किलहीन आदमी को कुछ नहीं मिलेगा।

इसलिए समाधान एक ही है – कक्षा 10 के बाद कलम के साथ कारीगरी। संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार "Dual Work System" को प्राथमिकता से लागू किया जाए। सप्ताह में तीन दिन कम्पनी या आईटीआई, दो दिन स्कूल। 18 साल की उम्र में डिप्लोमा और 20-25 हजार रुपये तनख्वाह। फिर क्या बदलेगा? 18 साल का स्किल्ड युवा कमाने लगेगा तो लड़की वाले नौकरी पूछेंगे, बेरोजगार नहीं कहेंगे। दहेज खत्म क्योंकि दोनों कमाने वाले होंगे। फैक्ट्री में लड़का-लड़की साथ सीएनसी चलाएँगे तो 3 साल में एक-दूसरे का आचरण परख लेंगे। कुण्डली फेंक देंगे। युवा मोबाइल असेम्बल करेगा, ड्रोन बनाएगा तो आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा। इससे 9 बड़े फायदे होंगेः युवा अपराध से बचेगा, जीडीपी 1.5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ेगी, माता-पिता का बोझ हल्का होगा, कर्जमुक्त ग्रेजुएशन होगा, महिला सशक्त होगी, भारत उत्पादक राष्ट्र बनेगा, कृषि में युवा की वापसी होगी, जातिमुक्त भारत बनेगा, रक्षा आत्मनिर्भर बनेगी। सरकार की जिम्मेदारी संविधान के अनुच्छेद 41 में लिखी है – राज्य काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। स्टाइपेण्ड राज्य के न्यूनतम वेतन का 50% + 2000 रुपये टॉप-अप करो। NAPS ऐप में रोज सेल्फी और जीपीएस। 55 लाख खाली पद 5 साल में भरो। माँ-बाप की सोच बदलो। बेटा 10वीं पास करे तो पूछो कौन सा हुनर सीखना है न कि कौन सा कॉलेज। लड़की वालों से अपील है जाति नहीं, तनख्वाह और आचरण देखो। लड़के से अपील है तैयारी नहीं, हुनर दिखाओ।

3 लाख साल पहले मानव ने पत्थर उठाया था। आज उसे मशीन उठानी है। बेरोजगारी मिटेगी तो लड़का 25 में शादी करेगा। शादी होगी तो घर बसेगा। घर बसेगा तो समाज बसेगा और समाज बसेगा तो भारत बसेगा। कबीर का आखिरी संदेश हैः –''बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।''– यानी पहले खुद स्किल्ड बनो, फिर दुनिया बदलेगी। स्किल्ड युवा होगा तभी स्वावलम्बी भारत होगा। जय स्किल्ड युवा। जय संविधान। जय भारत।

-मदन सिंह काला,
पूर्व आई.ए.एस अधिकारी

प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छह साल से पदोन्नति का इंतजार

- **राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है**

कबीकानेर, (निसं)। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक पद सोपान में सबसे अंतिम पायदान पर नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ सरकार का थर्ड ग्रेड टॉचर्र लगातार जारी है। राज्य सरकार की 5 जुलाई तक तबादलों से हटाई रोक को इस बार भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं किया है। उधर 6 साल से इनकी पदोन्नति भी कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। ऐसे में पद और स्थान दोनों परिवर्तनों का लाभ नहीं मिलने से करीब 1.22 लाख शिक्षक पदोन्नति व तबादला नीति के दो पाटों में पिसते महसूस कर रहे हैं।

शिक्षक नेता मोहर सिंह सलावद ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति भी छह साल से अटकी हुई है। अतिरिक्त विषय से स्नातक डिग्री की वैधता को लेकर चल रहे न्यायिक विवाद की वजह से लगभग 30 हजार शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो पा रही। शिक्षक संघ रेसटा का आरोप है कि सरकार के ढीले रवैये की वजह से ही मामला कोर्ट में ढीला चल रहा है। यदि ग्रेड थर्ड शिक्षक पदोन्नत होते तो द्वितीय थर्ड श्रेणी शिक्षक नियुक्त होने पर उन्हें तबादलों का लाभ भी मिल जाता।

राज्य में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतिम बार तबादले 2018 में हुए थे। उसके बाद से सरकारें तबादला नीति लागू करने का हवाला देते हुए उसे लगातार टाल रही है। इससे दूरदराज के इलाके में लंबे समय से नियुक्त लगभग 1 लाख शिक्षकों का तबादलों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। प्रतिबंधित 10 जिलों में तो कई शिक्षक 15-15 साल से घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 26 जून, 2026

द्वितीय ज्येष्ठ मास (शुद्ध), शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, विशाखा नक्षत्र सायं 7:16 तक, सिद्ध योग दिन 11:39 तक, बव करण प्रातः 9:16 तक, चन्द्रमा आज दिन 12:23 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-तुला, मंगल-वृष, बुध-कर्क, गुरू-कर्क, शुक्र-कर्क, शनि